आर आई से लेकर सी बी आई तक सब को मैं इनवैस्टीगेशन का काम सौपने के लिए तैयार हूं । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे मामले में सी बी आई को समय समय पर हम लिखते रहे हैं, जानकारी देते रहे है । जैसा आपको मालूम ही होगा विदेशों में जो भी तस्करी की इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उनके सम्बन्ध में इंटर-पोल जो एजंसी है उसकी मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता है । इंटरपोल की जो एजंसी हैं उन्होंने हर देश में अपनी अपनी एजंसी मुकर्रर कर रखी है । मारिशस में एक नैशनल क्राइम ब्यूरो करके एजंसी उन्होंने कस्टम वालों को दे रखी है । उसी तरह से टरपोल वालों ने सी बी आई के जो चीफ हैं डाइरेक्टर सी बी आई उनको दे रखी है । उनके साथ हम कारेसपौंडेंस में है, जानकारी उन से ले रहे हैं, उन से भी इनवैस्टी-गैशन कुछ हो रहा है । मैं आश्वासन दे सकता हूं कि इस सारे मामले में, इनवैस्टीगेशन के बारे में आप मुझ से ज्यादा न कहलवाएं क्योंकि इसमें बड़े डैलीकेट मामले इनवाल्व्ड हैं और एडवांस में मैं कुछ अधिक नहीं कह सकता हूं। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सारा प्रकरण जो अभी तक मिस्टरी बना हुआ हैं उस पर से पर्दा हटाने के लिए डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलीजेंस को विगोरस सर्च और थारो प्रोब करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं और जैसे ही उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट आयेगी मैं सदन को सूचना दे दूंगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : एक प्रश्न रह गया है । क्या धवन साहब ने टेलीफोन पर ओरल इंस्ट्रक्शंज दे रखी थीं कि जो माल इस तरह का जाए या आए उसको रोका न जाए ? क्या यह भी एक तथ्य है ।

श्री सतीश अग्रवाल : धवन साहब तो दिल्ली में रहते थे । आपने पूछा है कि उन्होंने इस प्रकार के कोई आदेश कस्टम के अधिकारियों को दे रखे थे कि इन बड़े बड़े वी आई पीज के या श्रीमती इंदिरा गांधी के जो साथी है उनके बक्से न खोले जाएं, उनके बक्सों की जांच न की जाए ।

उसमें 5 जने है । वह 5 जने वाले मामले का जिक्र जो आपने किया है उसका अगर आप विस्तार से अलग से प्रश्न पूछेंगे तो अलग से सूचना दे दूंगा । इन प्रश्नों में आपने उस बारे में जानकारी मांगी नहीं थी ।

सभापति महोदय : इस वक्त उनके पास जानकारी नहीं है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : कहिये साहब कि जानकारी नहीं है ।

सभापति महोदय : उन्होंने कह दिया है कि अलग से आप पूछेंगे तो वे उत्तर देंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा और सदन को सूचित कर दूंगा ।

18.31 hrs.

SUPREME COURT (NUMBER OF JUDGES) AMENDMENT BILL—*contd.*

MR. CHAIRMAN: Now we take up the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill.

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, अभी इस पर काफी बहस हो चुकी है. . . .

सभापति महोदय : आप केवल अपने संशोधन पर ही बोलें ।

डा० रामजी सिंह : इस पर बहस नहीं हो सकी है कि 13 से बढ़ाकर 17 जजेज क्यों किये जायें । इससे ज्यादा क्यों न किये जायें जजों की तादाद।...

सभापति महोदय : आपका तो अमेंडमेंट ही मूव नहीं हुआ । जब कल हुआ तो आप यहां नहीं थे । इसलिये आप अभी नहीं बोल सकते । अगर बोलना है तो थर्ड रीडिंग पर 2, 3 मिनट बोल लीजियेगा ।

We take up amendments to clause 2.

मंत्री जी इन अमेंडमेंट्स के बारे में कुछ जवाब देना चाहते हैं जो 6 अमेंडमेंट्स आये हैं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव : (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, हमारा भी क्रम संख्या 4 पर संशोधन है । मुझे भी बोलने का मौका दें ।

सभापति महोदय : जी हां, आप पहले बोलें आपका नाम पहले है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि मूल अधिनियम की धारा 2 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु यह कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 25 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों और सामाजिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों में से उपलब्ध उपयुक्त और अर्ह व्यक्तियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे ।"

सभापति महोदया, यह 17-12-73 का पिछली सरकार का एक उत्तर है जिससे साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जज शेड्यूल्ड कास्ट और शड्यूल्ड ट्राइब का नहीं है । इसी तरह से दूसरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह बताया कि हाई कोर्टस में शेड्यूल्ड कास्ट के तीन जज हैं । आन्ध्र प्रदेश में 1, मध्य प्रदेश में 1 और पटना में 1 । बैकवर्ड क्लासेज के बम्बई में 5, केरल हाई कोर्ट में 9 और मद्रास हाई कोर्ट में 6 । इस तरह से यह परसेंटेज है, जब कि देश के तमाम हाई कोर्टस में जजों की संख्या 351 के करीब होती है, और 67 के करीब जगहें खाली पड़ी हैं । उसमें से यह संख्या है इन वर्गों की जो कि समाज के दबे हुए लोग हैं । लेकिन इनमें भी योग्य आदमी यहां बिराजमान हैं । पर अभी तक उनके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है । मैं मंत्री जी का ध्यान खींच रहा हूं उस प्रस्ताव की तरफ जो नीति सम्बन्धी है । अगर आप चाहते हैं कि समाज में से विषमता हटे और जो 99 फीसदी आबादी के लोग उपेक्षित रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह ऊपर आयें और अगर उनमें पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं तो उनको संरक्षण देने के लिये नीति सम्बन्धी हमारा संशोधन है और इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी । यह संविधान के मुताबिक है । आर्टीकल 340(1) के अधीन राष्ट्रपति जी ने बैकवर्ड क्लासेज कमीशन के नाम से काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग बैठाया था जिसने कहा है कि कौन कौन लोग पिछड़े वर्गों में आते हैं । इसी तरह से शड्यल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट मौजूद है ।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि आज तक 30 सालों में क्लास 1 और क्लास

2 के अधिकारियों की जो संख्या है उसमें शैड्यूल्ड कास्ट के केवल 4 फीसदी और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग 1 या डेढ फीसदी आते हैं। इस तरह से समाज की 99 फीसदी जो आबादी है, वह पिछड़ी है, सर्वहारा है। पिछले 30 बरस में उसको हर जगह ठुकराया गया है। आज जमाना बदला है, उसी जनता के कारण आज हम लोग यहां लोक-सभा में जनता पार्टी की सरकार के रुप में बैठे हुए हैं। जनता पार्टी ने वादा भी किया है, चुनाव घोषणा-पत्र में स्पष्ट लिखा है कि 25 फीसदी क्लास-1 अफसरों में भी काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संरक्षण दिया जायेगा। पिछले 9 महीने में मैं सरकार का ध्यान कई बार इस ओर आकर्षित कर चुका हूं। सामाजिक विषमता मिटाने के बारे में नान-आफिशियल बिल भी मैंने पेश किया है। मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि वह योग्य हैं, विद्वान हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, इससे उनका कोई विवाद भी नहीं है, जब अच्छे लोग हाई कोर्ट में हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को मानने में कोई आपत्ति उन्हें नहीं होनी चाहिये।

इसलिये मैं चाहूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें ताकि जनता का इमेज और बढ़े और समाज की विषमता दूर हो, भेदभाव खत्म हो, सोशल और इकनामिक डिस्पैरिटी खत्म हो। यह एक नई बात जनता पार्टी की सरकार के लिये होगी कि जो समाज का आज का ठुकराया हुआ वर्ग है, उसको सुप्रीम कोर्ट में स्थान देने के लिये जनता पार्टी ने एक कानून बनाया है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदया, ला कमीशन ने जजेज के एप्वाइन्टमैंट के बारे में कुछ अपनी राय बनाई थी—

> "The question of appointment of persons as judges of High Courts and Supreme Court was considered by the Law Commission in their 14th report. Regarding Supreme Court appointment, the Commission recommended that a judge of the Supreme Court should have a tenure of at least 10 years. The Government in 1960 accepted the recommendation subject to the change that save in exceptional cases, the *minimum* should be ordinarily five years."

यह गवर्नमेंट स्वीकार कर चुकी है। ला-कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ही धारा 2 में मैंने यह संशोधन रखा है कि उसके साथ यह जोड़ दिया जाये—

> "परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसकी आयु नियुक्ति के समय साठ वर्ष से अधिक हो, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।"

चूंकि सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष की आयु में जज रिटायर होता है, तो कम-से-कम 60 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिये

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

ताकि यहां आकर वह 5 वर्ष तक सेवा कर सके। गवर्नमेंट इस सिद्धान्त को स्वीकार कर चुकी है 1960 में कि 10 साल नहीं कम-से-कम 5 साल। क्योंकि हाईकोर्ट के जजेज की रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आदमियों को लाया जाये जो कम से कम 5 साल तक सेवा लगातार कर सकें। अगर कोई व्यक्ति 62, 63 वर्ष का आ गया तो वह 2, 3 साल सेवा करने के बाद फिर रिटायर हो जायेगा, यहां पर थोड़ी काम की जानकारी होगी और वह चला जायेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

सभापति महोदय : श्री विनायक प्रसाद यादव।

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, एक मिनट हमें भी बोलना है।

सभापति महोदय : आप बीच में नहीं बोल सकते हैं, जिनके अमेंडमट हैं, मैं उन्हीं को बुला रही हूं।

श्री रामजी लाल सुमन : मुझे इसमें यह निवेदन करना है...

सभापति महोदय : निवेदन इस वक्त नहीं हो सकता है। आपका कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर है क्या? निवेदन ऐसे नहीं हो सकता है।

श्री विनायक प्रसाद यादव यहां नहीं हैं, इसलिये मिनिस्टर इसका रिप्लाई करें।

श्री शांति भूषण : सभापति महोदय, जो 3 तरह के संशोधन पेश किये गये हैं, कुछ में तो 17 की संख्या को बढ़ाने को कहा गया है या कम करने को कहा गया है, किसी ने 25 कहा है किसी ने 30 कहा है किसी ने उसे 15 के लिये कहा है।

जहां तक संशोधन का सम्बन्ध है मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत अधिक संख्या हम इसलिये नहीं रखना चाहते हैं कि जब जैसे जरूरत हो, हम पार्लियामेंट, संसद् के सामने आकर उसकी स्वीकृति लें। लेकिन फिर भी 17 हमने इसलिये माना है कि रोज-रोज हम संसद् में आकर 1, 1, 2, 2 या 6, 6 महीने बाद इस प्रश्न पर इसका समय लें तो यह उपयोगी नहीं होगा। इसीलिये हमने बीच का रास्ता लिया है कि 17 इस समय करें, 4 की बढ़ोत्तरी पहले करें, चाहे 2 अब करें और 2 बाद में करें लेकिन उसके बाद 17 से आगे की आवश्यकता हो तो संसद् का समय दोबारा लें।

माननीय सदस्य, श्री रूपनाथ सिंह यादव, अपने संशोधन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज के लिए 25 फ़ीसदी आरक्षण चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार इस कानून में इस तरह की बात

जा ही नहीं सकती हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा 7 जजिज होंगे, जब तक कि संसद् किसी कानून के द्वारा ज्यादा संख्या का निर्धारण न करे। इस अनुच्छेद के अनुसार पहले भी कानून लाये जा चुके हैं। उसी के अनुसार अब यह बिल लाया गया है जिस के अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 17 जजों का प्रावधान किया गया है।

संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि किस को जज बनाया जा सकता है, किस को नहीं बनाया जा सकता है, उस के लिए क्या प्रक्रिया होगी, किस की रीकमेंडेशन होगी और किस के साथ कनसल्टेशन किया जायेगा। जब संविधान के इस अनुच्छेद में इस बात की कोई चर्चा नहीं की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए जात-बिरादरी के आधार पर, या शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा बैकवर्ड क्लासिज के लिए, कोई आरक्षण किया जाये,—सरकारी नौकरी में क्लास वन आदि पदों के लिए आरक्षण करना एक भिन्न बात है—, तो फिर किसी कानून के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता हैं। वह असंवैधानिक होगा। इस लिए मैं इस प्रकार के संशोधन को मानने से मजबूर हूं।

माननीय सदस्य, श्री ओम प्रकाश त्यागी, ने भी एक संशोधन रखा है। जहां तक उन की भावना का सम्बन्ध है, मैं उस का आदर करता हूं। उन्होंने देखा होगा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां होती हैं, तो इस बात का विचार रखा जाता है कि वह न्यायाधीश कम से कम पांच साल तक सर्वोच्च न्यायालय में कार्य कर सके, क्योंकि अगर वह सर्वोच्च न्यायालय में थोड़े समय के लिए रहता है, तो उस की उपयोगिता उतनी नहीं रहती है, जितनी कि उस स्थिति में होती है, जबकि वह कई वर्ष तक वहां पर कार्य कर सके।

श्री रूपनाथ सिंह यादव : हाई कोर्टस् में 23 जज मौजूद हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज के हैं।

श्री शान्ति भूषण : यह कोई नहीं कह रहा है कि उन को नियुक्त करने के बारे में विचार नहीं हो सकता है, या अगर मुख्य न्यायाधीश उन की संस्तुति करें, तो उन के बारे में विचार नहीं हो सकता है। लेकिन कानून में इस प्रकार का कोई आरक्षण कर देना संविधान के विपरीत होगा कि उन्हें इस पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाये, या अगर उन से ज्यादा उपयुक्त दूसरे जज हों, तो भी उन्हें सिर्फ इस आधार पर नियुक्त कर दिया जाये कि वे शिड्यूल्ड कास्ट्स या बैकवर्ड क्लासिज के हैं। अगर संविधान में ऐसा आरक्षण होता, तो दूसरी बात थी।

[श्री शान्ति भूषण]

श्री ओम प्रकाश त्यागी ने कहा है कि इस कानून में यह संशोधन कर दिया जाये कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति की इस पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती है। जब संविधान इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाता है कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को नियुक्ति नहीं हो सकती है, तो मैं समझता हूं कि कानून में ऐसा प्रतिबन्ध लगाना संविधान के विपरीत होगा। यह दूसरी बात है कि नियुक्ति करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाये, ला कमीशन ने जो कहा है, उसे भी सामने रखा जाये।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सरकार ने इसे स्वीकार किया है।

श्री शान्ति भूषण : इसी लिए तो जब भी नियुक्तियां होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। माननीय सदस्य ने देखा होगा कि हाल ही में जो दो नियुक्तियां हुई हैं, वे ऐसे लोग हैं, जो पांच साल से ज्यादा समय तक सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। लेकिन इस प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबन्ध लगा देना, जब कि संविधान में ऐसा कोई प्रतिबन्ध न हो, संविधान के अनुकूल नहीं होगा। इस लिए मैं इस संशोधन को मानने में अपने को असमर्थ पाता हूं।

MR. CHAIRMAN: Mr. Laxmi Narain Nayak, do you press your amendment?

SHRI LAXMI NARAYAN NAYAK: I withdraw it, Madam.

MR. CHAIRMAN: Does the hon. Member have the leave of the House to withdraw his amendment?

HON. MEMBERS: Yes.

Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, श्री रूपनाथ सिंह, क्या आप अपने एमेंडमेंट को प्रैस करना चाहते हैं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव : मेरा सबमिशन है कि जब मंत्री महोदय आईंदा संविधान संशोधन बिल लायें, तो वह एक काम्प्रिहेंसिव बिल लायें, जिसमें यह व्यवस्था भी कर दी जाये।

MR. CHAIRMAN: Please tell me whether you want to withdraw your amendment or not?

श्री रूपनाथ सिंह यादव : मैं प्रैस करता हूं।

MR. CHAIRMAN: All right. I will put amendment No. 4 to the vote of the House.

Amendment No. 4 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Does Shri Tyagi want to press his amendment No. 5?

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं वापस लेता हूं।

MR. CHAIRMAN: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

Amendment No. 5 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: I will now put amendment No. 8 by Shri Vinayak Prasad Yadav to the vote of the House.

Amendment No. 8 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I beg to move:

"That the Bill be passed"

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed"

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : मैं केवल इतना ही आप के माध्यम से विधि मंत्री से पूछना चाहूंगा कि किस डर से वे अभी अधिक संख्या उपस्थित नहीं कर रहे हैं ? वह देखें 1950 में संख्या 7-8 थी, 1956 में 10 हुई, 1960 में 13 हुई, तो हर पांच दस वर्ष के बाद यह लाते जायें, ठीक है, संविधान की धारा 124 के अन्तर्गत यह आप को अधिकार है, आप लायेंगे लेकिन आप यह भी देखें कि एक तो आबादी बढ़ रही है, दूसरा कारण आपने बताया कि नये केसेज की पेशियां ज्यादा हो रही हैं, तीसरी बात आप ने कही कि बहुत सी पडेंसी है तो ये तीनों कारण तो आप के हैं और फिर आप कहते हैं कि "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड" और यह भी आपने ही कहा है कि "जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड", तो इन दोनों दृष्टिकोणों से अगर आप सोचते हैं कि न्याय जल्दी दें तो संख्या ज्यादा होनी चाहिए । यदि आप चाहते हैं कि न्याय देने में जल्दबाजी न हो तो भी संख्या आपको ज्यादा देनी चाहिए । तीसरा कारण भी है कि आप देखते हैं कि न्यायाधीशों के लिए कोई इस प्रकार की आचार संहिता भी बनाने में बड़ा संकोच हो रहा है तो फिर जिस कायदे से चल रहा हैं उसी कायदे से चलेगा अभी सभापति महोदया चाहें तो तीन मिनट में मुझे भाषण समाप्त करना होगा लेकिन न्यायाधीशों को आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि तीन महीने या छः महीने में फैसला दे दें । इसलिए भी आपको अधिक संख्या रखने में लाभ होगा और मुकदमों के फैसले जल्दी होंगे ।

संविधान की धारा 133 के अन्दर हम देखते है कि एक बहुत परेशानी सिविल केसेज में होती है । उसके (ए) और (बी) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट सबस्टेंशियल मामलों में जो केसेज लेते हैं, यानी अमीरों के ही केसेज सुप्रीम कोर्ट देखती है, गरीबों के लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं है । उसी तरह धारा 134 के अन्तर्गत क्रिमिनल जूरिस्डिक्शन या दाण्डिक अधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय को है उसमें भी आप देखें बहुत सी बाधायें हैं । यानी उसमें भी हम सामान्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं । यही कारण होता है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल अमीरों के लिए बन जाता है, गरीबों की पहुंच न तो सिविल केसेज में हो सकती हैं न क्रिमिनल केसेज में हो सकती हैं ।

तीसरी बात है कि संविधान की धारा 136 के अनुसार हमारे विधि मंत्री जानते हैं कि 80 प्रतिशत स्पेशल लीव के केसेज जो होते हैं वे कच्ची पेशी में ही खत्म हो जाते हैं । इसके स्टैटिस्टिक्स हैं कि 300 केसेज में 30 एडमिट होते हैं । इसी तरह से हम देखते हैं कि तीनों कारणों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जो न्याय नागरिकों को दे सकती हैं वह न्याय नहीं दे पाती हैं । संविधान की धारा 142 के अनुसार लिखा हुआ है कि कम्प्लीट जस्टिस चाहिए लेकिन कम्प्लीट पावर्स भी कोर्टस को नहीं देते हैं ।

"The Supreme Court, in the exercise of its jurisdiction, may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it."

तो इस प्रकार के सम्पूर्ण न्याय भी करने का अवसर सर्वोच्च न्यायालय को नहीं होता है । सर्वोच्च न्यायालय में भी ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं जिसको अनसेटिसफैक्टरी जजमेंट कहते हैं । इसलिए हम समझते हैं बढ़ती हुई

[डा० रामजी सिंह]

आबादी और केसेज को जो पेंडेंसी है, ज्यादा पेशियां और 133 के अन्तर्गत 134 के अन्तर्गत 136 के अन्तर्गत और 142 के अन्तर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार सीमित हो जाते हैं उन अधिकारों को बढ़ाना चाहिए नहीं तो मार्क्स की बात सही होगी।

justice in the interests of the stronger.

इसीलिए मैंने विधि मंत्री जी से निवेदन किया था कि संख्या 21 बढ़ाई जाए ताकि आपने जो संकल्प लिया है कि तीन वर्षों में सारे पुराने मुकदमें समाप्त कर देंगे वह आप कर सकें नहीं तो हम बैठे रहेंगे और पांच वर्षों के बाद फिर आपके संकल्प गलत हो जायेंगे। इसलिए आप उदारता दिखायें ताकि आप अपने संकल्प को पूरा कर सकें।

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): I support this Bill and I welcome its provisions.

It is being argued that the number of Judges could have been slightly increased, but as the hon. Law Minister just now said—I agree with him—it is only an enabling provision. I do not think he wants that all these extra Judges be appointed straightaway. If the number of Judges becomes too large, then the Bench will be somewhat unwieldy. I think it is in the interests of justice also that the Supreme Court has a certain sense of compactness. Its working becomes possible only if the number is not too large or too small.

I feel that the amenities and facilities to the Judges at the Supreme Court, High Court and even district level, should be looked into and they must be give more amenities. After all, the independence of the judiciary is partly and significantly dependent on the kind of facilities, amenities and comforts that the Judges are entitled to have.

Please remember that the number is to be added on the basis of quality. I am glad that the hon. Minister at the second reading gave us this assurance that he will see to it that the Judges are appointed not on the basis of caste, language or religion but on sheer competence. I am with him when he says—the whole House wants it that way—that more and more scheduled castes, scheduled tribes and backward classes persons through education, training and equipment should become Judges. None will be happier than ourselves.

We do not want it to be the privilege of the so-called higher castes, but these appointments should not be made on the basis of caste or class but only on the basis of competence.

The hon. Minister himself says that the number of institutions has been galloping. In 1960 it was 3,241 and in 1976 it became 8,254. Pendency has gone up from 2,319 in 1960 to 14,109 in 1976. He himself is saying that the arrears are increasing constantly.

I want to stress at this stage the citizen's angle. We talk in terms of the Judges and the advocates, but who is there to talk about the citizen's point of view? Only the citizens' representatives in this august House can talk about the interests of the litigants. They have no spokesman because they cannot go to the court, but at least they can come to this House through their chosen representatives. That is why I am taking this opportunity to emphasize this point that the citizens are felling continuously more and more harassed and helpless. Ultimately, if the administration of justice means, it is for the benefit of the people, then this aspect of the matter has to be emphasized that the lawyers and judges will function in such a way that the administration of justice is promoted.

Here, I would like to make two points. The hon. judges—I would not like to speak about individual judges—universally all of them are working very hard. But we are carrying a feeling that the hon. judges parti-

cularly in the High Court, some of them, and also in the lower courts, with exceptions of course, if I may say so, have also to change their moods and habits and decide judiciously and also fairly quickly. May I point out in this regard one thing? There is need for home work and hard work for the judges. The home work and the hard work on the part of judges is as important and as essential as it is for Member of Parliament, Ministers, Government servants, professors, teachers and anybody else. We carry a feeling, the people at large carry a feeling, that the judges particularly in the High Courts and the lower courts do not give ample time and attention to home work and hard work for the kind of justice which they have to give after hearing the cases. The Supreme Court Judges burn their midnight oil. I would like the hon. Minister to contradict if he can, whether it is true of High Court judges. It is not true. Therefore, my point is that hard work and home work are important and essential for them. That also must be looked into.

A word or two about the amenities provided particuarly at the district and the lower level. There are areas in Gujarat, in Saurashtra, in Orissa, in Tamil Nadu and in Kerala, where judges do not have even ordinary facilities like, toilet, and there are cases where magistrates go home to answer the call of nature and come back to work. This kind of a thing is not very satisfactory. The hon. Minister must go into this aspect also. I am taking this opportunity to point out that magistrates and lower level judges are undergoing some of these difficulties.

Lastly, as I was saying in the beginning, the litigants' interest, the litigants' point of view and their anxiety for speedy and inexpensive justice must be looked into. The hon. Prime Minister, Shri Morarji Desai, and the Law Minister have of late been talking about speedy justice and less expensive justice. I want to go on record to say that the appointment of judges must be made in a manner which may lead to less corruption. Therefore, any provision that you may make to see that judges are appointed in a way that will bring in an atmosphere of cleanliness, efficiency and incorruptibility, I am all for it and by all means, you do it. But the overall consideration should be that the administration of justice is the responsibility of the Minister of Law. He is not merely the Minister of Law. He is also the Minister of Justice. He is accountable to us in Parliament to tell us whether the people of India are getting justice or not. Therefore, he must also take an account from the judiciary. He cannot take on account from the judiciary being in the Government. He can take an account from the judiciary by telling them politely that he has to give a report to Parliament about what they are doing. The Chief Justice of the High Court can tell his colleagues to work hard. He can tell them, "Don't come at 12 O' Clock. Come at 11 O' Clock. Don't go early; don't give constant adjournments, adjournment after adjournment of the cases." The advocates want adjournments. They appear for five minutes and ask for an adjournment of the case. They charge a fee for that. The people go on paying fees. It goes on for years. No solution to the problem.

I want to emphasize that the independence of judiciary does not mean that judiciary should be irresponsible and unaccountable. The judiciary is responsible and accountable to Parliament and, in this way, it is accountable to the community at large. As I said, the Minister of Law is also the Minister of Justice. Justice must be properly carried out. We want our judges not to be touched unless, of course, there is a gross misconducts on their part. The Parliament has got the power under the Constitution to remove a judge. We hope, that will not happen. But because they are not to be touched, that does not mean that they have no account to give to Parliament and to the people. That must not take place. That is all I have to say.

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : माननीय सभापति महोदया, उच्चतम न्यायालय के जजों की संख्या में वृद्धि के बारे में जो बिल रखा गया है और उसमें श्री रूपनाथ सिंह यादव ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार ने जो वायदे जनता के सामने किये हैं उन वायदों को अविलम्ब पूरा किया जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि हम कथनी और करनी में एकरूपता स्थापित करें। श्री रूपनाथ सिंह यादव ने जो संशोधन दिया है वह संविधान में जो शेडयूल्ड कास्ट्स के बारे में आरक्षण की व्यवस्था है और जो संविधान के निर्माताओं की भावना रही है उसको पूरा करता है। जहां तक बुद्धि का सवाल है डा० अम्बेडकर ने संविधान बना कर इस बात को साबित कर दिया है कि बुद्धि में हिन्दुस्तान का शोषित और पीड़ित समाज दूसरे लोगों से कम नहीं है। इसलिए जब शीर्षस्थ स्थानों पर इन जातियों के लोगों को नहीं बिठाया जाता है तो इस देश के इन लोगों का विश्वास सरकार पर से टूटने लगता है और वह विश्वास इस सरकार से टूटना शुरू हो गया है। जब तक शीर्षस्थ पदों पर हिन्दुस्तान के शोषित और पीड़ित लोगों को आसीन नहीं कर देते तब तक निश्चित रूप से इस देश में न्याय मिलने वाला नहीं है।

जहां तक न्याय का सवाल है मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो मान्यता है जो परम्परा चल रही है उसमें न्याय उन लोगों को नसीब नहीं हो पाया है जिनको वह मिलना चाहिए था। उनके लिए न्याय भी महंगा हो गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि संविधान में जो आरक्षण है हर कदम पर हमें उसका स्वागत करना चाहिए और खुले दिल से उस भावना को लेकर काम करना चाहिए जो संविधान के अन्दर निहित है।

मैं एक बात नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं और वह यह है कि जब हम आरक्षण की बात करते हैं और जब हम आई० ए० एस० और पी० सी० एस० को देखते हैं तो वहां पर यह पाते है कि आई० ए० एस० में उनका रेप्रेजेंटेशन सिर्फ एक परसेंट या डेढ़ परसेंट ही है। यह क्या हमारी मान्यता है नीयत क्या है? सब से महत्वपूर्ण बात इस चीज को देखने की हैं। आज विधि मंत्री जी कानून के दायरे में हमें घसीट सकते हैं हमें समझा सकते हैं लेकिन व्यवहारिक पक्ष क्या है। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं और दोहराना चाहता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और हिन्दुस्तान के दूसरे शीर्षस्थ पदों पर पुलिस में न्यायालयों में हिन्दुस्तान के शोषित और पीड़ित लोगों को रखें। जब ऐसा होगा तभी डा० लोहिया और डा० अम्बेडकर के सपनों का भारत बन जाएगा इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि श्री रूपनाथ सिंह यादव का जो क्रांतिकारी संशोधन है उसको वे स्वीकार करें।

SHRI SHANTI BHUSHAN: Hon. Member, Dr. Ramji Singh, has drawn attention to the need for having many more judges. I would like to say this for the consideration of the hon. Members: should it be that the High Courts are not in a position to do justice in individual cases and that every case must go to the Supreme Court and only then justice would be done? If one has that impression, then I would like to say with the utmost humility that that impression would be wrong because even the High Courts are very high courts, very high in the hierarchy of courts. It is the High Court which is supposed to dispose of matters in individual cases, which is supposed to render justice in individual cases. That is not the function of the Supreme Court. If we expect the Supreme Court to do justice in individual cases, then we will really be

converting the Supreme Court into all the High Courts put together because each case, after going to the High Court, would have to go to the Suprem Court also in order to be decided, whether the judgment was right or should have been different. In that case, the Supreme Court would have to be as large as all the High Courts put together; its level would come down to the same level as that of High Courts, with the result that we will have to choose whether the High Courts should be there or the Supreme Court should be there. There would be hardly any point in having two courts of equal size with the same calibre in judges. If there is to be a court, then evidently the position should be that that Court must deal with a restricted category of cases. That is how it will be enabled to maintain its higher capacity, status, and so on. That is why; this hierarchy has been so formulated: the cases which can be disposed of simply are disposed of at the lower level; cases which involve more complicaed questions go up to a higher level; cases which involve giving a direction to the development of law or which require unifying the law in the country, namely, resolving any difference of opinion which may be there in the High Courts of different States, have to go to the Supreme Court. In fact, that is a matter which is now engaging the attention of the Supreme Court as to whether the policy which has been adopted by the Supreme Court in the past in granting leave under article 136 very liberally, in trying to have the role of doing justice in every individual case, has really served the purpose for which the Supreme Court has been created. Or, is it not that the present situation which is there, namely, that the Supreme Court is locked up with so many pending cases and cases cannot be disposed of even in five or six years, can be attributed to a very liberal approach in granting leave under Article 136, because sometimes a person in trying to de good for a large number of people incapacitates himself from doing good to anybory? For example take the case of the United State Supreme Court. There, even increasing the number of Judges would not do any good, because all the judges have to sit in one bench. The number of judges there is eleven; even if you make it thirty-one, they would be hearing the same number of cases, because they have all to sit together, not in different benches. And, there fore, if they had also been thinking of liberally correcting every kind of error in the decisions of every court. then they would have also failed in serving the purpose for which they have been created. Now. a thinking is gaining ground and I am happy to say that the Supreme Court is applying its mind to these problems and taking stock of these problems to see as to what should be the role of the Supreme Court. so that it can continuously perform that role with some kind of a self-imposed limitation. I do not say that it is for anybody else to do, it is for them to consider as to what should be its policy and where it should limit its own jurisdiction. I am very happy that these matters are being increasingiy thought by the people who should think about them.

Prof. Mavalankar has drawn the attention of the Hon. Members of the House to very important questions. He mentioned about the amenities for the judges. I would like to state for the information of the hon. Members that last year, a lot has been done in regard to the amenities; for instance, apart from salary Rs. 3500/- for the High Court Judge and Rs. 4000/-for the Chief Justice. a provision was made for a free-furnished residence for them; a conveyance allowance of Rs. 300/- was given and an increase to the extent of 40 per cent was provided for in their pension. These things have been done, but nobody can say that even now the conditions are as one would like them to be.

All said and done, India is after all a poor country. Those who accept judgeship do so on account of a pas-

[Shri Shanti Bhushan]

sion to do national service, to do their duty. We have very eminent judges; if they had decided to continue in the bar, they would have been minting money like anything, but it is their passion that made them to accept the judgeship. After all, one must realise and I am happy to say that people with intellectual pursuit, know the limitations of money, they know that money is not a very attractive thing. They know the limitation of what they can do with the money. As I had once the occasion to say, the judges in our country live in the hearts of our people, because the people have respect for them; they live in the minds of men, because our people have admiration for their intellectual pursuits. These are the incentives for these judges. A little increase in the amenities etc. is not the real thing for them. Even if you increase the amenities, salaries etc. if they are really money-minded, they would not be tempted to these offices and accept the judgeship. Anybody who comes to the judiciary really comes for a life of sacrifice, a life of service. It is these noble ambitions which make these people to accept the judgeship. We are very happy that there are a large number of people in this country who with this noble ambition accept the judgeship and keep on discharging their duties in a very appreciable manner.

The hon. Member has also drawn attention to the fact, and has said very correctly that so far as the Supreme Court judges are concerned, there has been a long standing uniform tradition of hard work, burning mid-night oil and doing hard work in a very big way. Not a single person can say that any Supreme Court judge lives a life of peace. They live a very had life, uniformly each and very one of then. Prof Mavalankar said and with great humility I would like to agree with him that the same cannot perhaps be said uniformly about each and every Judge at the lower level including the High Court level. We are very happy and I am very happy to say that even in the High Courts, there is a considerable number of Judges who are very hard working and who burn midnight oil and they do as hard work as any Judge of the Supreme Court. But, at the same time, there are other Judges also—after all the number of Judges in India is more than 300—and the same thing cannot be uniformly said about all the Judges. I hope that in this new atmosphere which is being created in the country, in this new regard and new respect for the independence of the judiciary, in the new regard which the people of India have acquired for the judiciary, the judiciary would also be responsive as Prof Mavalankar has said and each and every Judge would consider that he owes it to the people of India who hold them in such high regard that they must do their very best so far as discharge of their duties towards the people of India is concerned. I hope not a single Judge in the country would be found wanting in giving his utmost, in making it a life of dedication, in doing his utmost to the cause of justice which is the most sacred duty that one can think of and which is much more beyond that any person can really give to a people.

Then Prof Mavalankar said that if the judiciary is to be independent and if the administration of justice has to be independent as in a democracy it must be, namely that each individual Judge must only consult his own conscience and the laws of the land in order to decide an individual case and he should not brook any kind of interference, direct or indirect and from any quarter or direction so far as the decision of the individual case is concerned. That goes so far as the independence of the judiciary is concerned to which this country is now so fully committed that this principle of independence of judiciary can never be destroyed. At the same time, I would like to say that Prof Mavalankar has very rightly pointed out that while the judiciary is in-

dependent, it does not mean that it is not responsible. Obviously, every institution which has been created by the people for the people for doing service to the people, cannot be really regarded constitutionally as an irresponsible institution. It is really accountable to the people in the ultimate analysis. The manner in which administration of justice is carried on, namely, as to whether it has really served the purpose for which the institution has been created, whether the laws of procedure, other laws and practices which are enforced in the courts of law are adequate and sufficient and proper to provide that there shall be quick justice and at the same, undiluted justice and that justice would neither be diluted nor hurried— a synthesis has to be found between both these requirements in that sense for administration of justice also— in regard to all these matters there is the ultimate accountability to the people and as he has very rightly said that that is why there is a functionary in the government who is known not merely as the Minister of Law but he is also known as Minister of Justice. In fact, recently in the Commonwealth Law Ministers' Conference, this aspect was highlighted and in the final communique which was adopted in the conference, one paragraph said—because sometimes some people tend to think that even if normally a government becomes accountable to the Parliament and through the Parliament to the people of India even in regard to the administration of justice, as if this is violative of the concept of the independence of the judiciary, it was made clear by a speical paragraph in that communique that it is not so because even in the administration of justice in a general way and not in regard to any individual case, ultimately, the government cannot forfeit, cannot abdicate its reponsibility to the Parliament and through the Parliament to the people of India....

PROF P. G. MAVALANKAR: That is right.

SHRI SHANTI BHUSHAN: With the result how administration of justice is carried on, whether the manner in which administration of justice is carried on is giving the fullest satisfaction to the people of India is a matter on which the government is accountable to the Parliament and through the Parliament to the people of India and that is why in a sense the judiciary of the country is also responsible to the people of India. They have to have due regard as to what are the requirements of justice, how they have to function, how they have to work and so on, so that the purpose for which this Institution has been created would really serve the purpose for which it was meant.

PROF P. G. MAVALANKAR: I would like the hon. Minister to say somthing about the inadequacy of certain basic amenities, at the lower level, no toilets etc.

SHRI SHANTI BHUSHAN: So far as lower level is concerned and basic amenities are concerned, we know that our lower judiciary, even lower than the High courts, namely, Magistrates, Munsiffs and so on, have to work under very arduous conditions. Increasingly now the importance of this matter is being felt. A lot is being done in various States. In the Planning Commission and other bodies, increasingly, the importance of administration of justice is coming to be realised. Because, it is only the proper administration of justice which affects every other field of governmental activity. In other words, no field of governmental activity is untouched by the administration of justice.

Proper, quick, speedy and fair administration of justice can facilitate the enforcement of so many other sections apart from giving general satisfaction to the people of India, apart from strengthening the rule of law which is necessary in democracy. All these are now being increasingly realised. And of course, within the financial constraints, which a poor

[Shri Shanti Bhushan]

country like India would have, increasing attention must be paid and emphasis must be laid towards ameliorating conditions etc. I have no doubht that in the present climate which has been created, all this will be done to the extent possible.

One last point about the reservation for Scheduled Caste people.

I would like to make the position clear that we would be happy—nobody would be happier than me—if we find more and more members of the Scheduled Castes and the Backward Classes not only in the highest judiciary of our country, but in every highest position in the country. In fact that day would be a very happy day indeed because for centuries and centuries these sections have been entirely neglected. The time has come when that neglect should not be there. But, at the same time, while it is said that there should be no neglect, each one of us must feel happy that they occupy more and more of the high places.

At the same time, so far as Reservation as such is concerned, the Constitution does not contemplate a Reservation and therefore a provision for Reservation in an Act of this kind cannot be provided.

I agree with Prof. Mavalankar when he says that it is not caste considerations which can be the predominent considerations in these matters. But, at the same time, there should be no prejudice against caste also. He has himself said it. There should be no prejudic whatsover. If, however, on account of any prejudice, people belonging to the so-called scheduled castes and backward classes are neglected, certainly, it would be a very wrong think. These communities have produced some of the most brilliant people whom we have. Dr. Ambadkar is one such example. It is difficult to say that he was not one of the most brilliant lawyers produced by this country. But, at the same time, we are nappy that, while in the earlier years there were no scheduled caste Judges m the High Courts, now we are finding that scheduled caste Judges are there in many High Courts and even more are going to be appointed. I think I am not letting out a secret when I say that even more of the Judges belonging to the Scheduled Castes are likely to be appointed in the near future.

I hope that the attitude of the Government would be appreciated by the Hon. Members and that they would not have any cause for any grievance against the procedure which is being evolved and what is being done by the Government.

With these words, I express my grateful thanks to all the hon. Members of the House for lending their support to the provisions of the Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

19-20 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 22, 1977/Pausa 1, 1899 (Saka).

GMGIPND—I.—2087 LS—28-1-78—900.